



योगी सरकार का बड़ा शिक्षा अभियान: पढ़ाई में पीछे छूटे बच्चों के लिए शुरु होगा 'केच-अप शिक्षण अभियान'

RNI No.- DLBIL/26/A3806

नईदिल्ली, शनिवार, 01 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक
वर्ष- 01 अंक-02 पृष्ठ-04
मासिक मूल्य- 50 रुपए

असम की बाढ़ ने छीना सब कुछ: तबाही के बीच जिंदगी फिर से संवारने की जंग

जितेन्द्र कुमार

असम एक बार फिर भीषण बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश और ब्रह्मपुत्र नदी समेत उसकी सहायक नदियों के उफान ने राज्य के कई जिलों को जलमग्न कर दिया है। हजारों परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, खेती की जमीन पानी में डूब गई है, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि लाखों लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। कई पीढ़ियों का कहना है कि इस बाढ़ ने उनसे ‘सब कुछ छीन लिया’ और अब उन्हें अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

बाढ़ का सबसे बड़ा असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ा है, जहां अधिकांश लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। धान, सब्जियां और अन्य फसलें पानी में पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। किसानों ने बीज, खाद और सिंचाई पर अपनी पूरी पूंजी लगा दी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी महीनों की मेहनत बाढ़ के पानी में बह गई। कई परिवारों के सामने अब रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। घरों के डूब जाने से हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। स्कूलों, सामुदायिक भवनों और सरकारी इमारतों को अस्थायी राहत शिविरों में बदल दिया गया है। यहां भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से कई शिविरों में भीड़ और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। बच्चों की पढ़ाई पर भी बाढ़ का गहरा असर पड़ा



स्कूल यूनिफॉर्म बाढ़ में बह गई हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना ​​है कि लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं के सामने भी बड़ी चुनौती है। बाढ़ के बाद दूषित पानी के कारण डायरिया, हैजा, टाइफाइड और त्वचा संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं, जगह-जगह जमा पानी मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें राहत शिविरों में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का इलाज कर रही हैं और साफ पानी तथा स्वच्छता बनाए रखने की अपील कर रही हैं। बाढ़ का असर केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। असम का प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है। यहां रहने वाले एक सींग वाले गैंडे, हाथी, हिरण और अन्य वन्यजीव ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। इस दौरान कई जानवर सड़कों को पार करते समय

दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। वन विभाग और स्वयंसेवी संगठन लगातार वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए निगरानी



कर रहे हैं। बचाव और राहत कार्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, भारतीय सेना, वायुसेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार जुटे हुए हैं। नावों और हेलीकॉप्टरों की मदद से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई इलाकों में जहां सड़क संपर्क टूट गया है, वहां हवाई मार्ग से खाद्य सामग्री और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक बारिश की घटनाएं पहले की तुलना में अधिक तीव्र और अनियमित हो गई हैं। इसके अलावा वनों की कटाई, नदी किनारों का कटाव, आर्द्रभूमियों का सिकुड़ना और अनियोजित शहरीकरण भी बाढ़ की गंभीरता बढ़ाने वाले प्रमुख कारण हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि केवल राहत कार्य पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि दीर्घकालिक समाधान के लिए एक सींग वाले गैंडे, हाथी, हिरण और अन्य वन्यजीव ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। इस दौरान कई जानवर सड़कों को पार करते समय

परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। क्षतिग्रस्त घरों, फसलों और बुनियादी ढांचे का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि पुनर्वास कार्य जल्द शुरू किया जा सके। किसानों के लिए मुआवजा, मकानों के पुनर्निर्माण और सड़कों-पुलों की मरम्मत जैसी योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है।

इस भीषण आपदा के बीच इंसानियत की कई प्रेरणादायक तस्वीरें भी सामने आई हैं। स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संगठन, युवा और सामाजिक संस्थाएं राहत सामग्री वितरित कर रही हैं। कई मछुआरों ने अपनी नावों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, जबकि युवाओं ने राहत शिविरों में भोजन और दवाइयां पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि कई इलाकों में पानी धीरे-धीरे उतरना शुरू हो गया है, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। हजारों परिवारों को अपने घर दोबारा बनाने होंगे, किसानों को फिर से खेती शुरू करनी होगी और बच्चों को स्कूल लौटना होगा। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन असम के लोगों ने हर संकट में अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और साहस का परिचय दिया है। यह बाढ़ केवल एक प्राकृतिक

आपदा नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों की गंभीर चेतावनी भी है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में ऐसी त्रासदियां और अधिक विनाशकारी हो सकती हैं। फिलहाल पूरे देश की निगाहें असम पर हैं, जहां लोग उम्मीद, हिम्मत और एकजुटता के सहारे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।

जापान में 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद मॉल में भीषण विस्फोट, कई लोगों की मौत, राहत-बचाव अभियान जारी

जितेन्द्र कुमार

जापान में आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने कुछ ही मिनटों में भयावह तबाही का रूप ले लिया। भूकंप के तेज झटकों के बाद एक व्यस्त शॉपिंग मॉल में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस दोहरी आपदा में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। कई लोगों के मलबे की फंसे होने की आशंका के बीच राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन व्यवस्था लागू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भूकंप उस समय आया जब मॉल में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे थे। अचानक धरती जोर-जोर से कांपने लगी, जिससे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। दुकानों की अलमारियां गिर गईं, शीशे टूट गए और कई जगहों पर छत का हिस्सा भी नीचे आ गया। लोग किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को हिला दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद मॉल से काले धुएं का विशाल गुबार उठने लगा। आग तेजी से कई दुकानों तक फैल गई और इमारत का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। मलबे में कई लोग दब गए, जबकि आसपास खड़े वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपने परिवार के सदस्यों की तलाश में इधर-उधर दौड़ते दिखाई दिए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस, एम्बुलेंस



रहा है कि भूकंप के दौरान गैस पाइपलाइन या बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा होगा, जिससे गैस रिसाव हुआ और बाद में विस्फोट हो गया। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि विस्फोट के वास्तविक कारण का पता विस्तृत तकनीकी जांच के बाद ही चल सकेगा। विशेषज्ञ पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रहे हैं।

जापान सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रणाली को तुरंत सक्रिय कर दिया है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सेना, दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन एजेंसियां मिलकर राहत कार्य चला रही हैं। पड़ोसी क्षेत्रों से अतिरिक्त राहत दल और भारी उपकरण भी प्रभावित इलाके में भेजे गए हैं। सरकार ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। भूकंप के कारण पूरे क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बिजली और पानी आपूर्ति बाधित हो गई है। गैस सप्लाई एहतियात के तौर पर बंद कर दी गई है ताकि कोई और दुर्घटना न हो।रेल सेवाएं और कई सड़क मार्ग भी अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं, जबकि इंजीनियर पुलों और इमारतों की सुरक्षा जांच कर रहे हैं। प्रशासन ने स्कूलों, सामुदायिक भवनों और खेल परिसरों में अस्थायी

पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, X से मांगी यूजर्स की पूरी जानकारी

राजिस्ट्रेशन विवरण, आईपी एड्रेस, लॉगिन हिस्ट्री, डिवाइस की जानकारी

और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ताकि संबंधित यूजर्स की पहचान की जा सके। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह साइबर अपराधों की जांच में अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभी जांच शुरुआती चरण में है और किसी शिकायतें मिली थीं जिनमें आरोप लगाया गया था कि X पर कुछ अकाउंट्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र, अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। शिकायतों की प्रारंभिक जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल को विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सौंपी। जांच के तहत पुलिस ने को एक आधिकारिक नोटिस भेजकर उन अकाउंट्स से जुड़ी जानकारी मांगी है जिनसे कथित तौर पर विवादित पोस्ट किए गए। पुलिस ने अकाउंट



अंजली सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर)

पर कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियों को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस

मनुस्मृति के एक कथित अंश का उल्लेख करना शुरू किया, जिस पर सत्ता पक्ष ने फिर विरोध दर्ज कराया। लगातार हंगामे के बीच सभापति ने दोबारा हस्तक्षेप करते हुए उनसे कहा कि वे विधेयक से जुड़े विषयों पर ही अपनी बात रखें।

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मनुस्मृति का उल्लेख किए जाने पर सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसके जवाब में सदन के नेता जेपी नड्डा ने खड़गे के बयान पर कड़ी

आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह के वक्तव्य से समाज में द्वेष और अशान्ति का वातावरण पैदा होता है। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के मूल पाठ को प्रमाणित किया जाना चाहिए। जिस पुस्तक का उल्लेख किया गया है, वह मूल पाठ नहीं है। पहले यह प्रमाणित किया जाए कि वह प्रामाणिक है। नड्डा ने सभापति से आग्रह किया कि मनुस्मृति के बारे में कही गई बातों को सदन को कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया जाए।

धर्मेन्द्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से दिया इस्तीफा, X पर पोस्ट कर दी जानकारी



उमा सक्सेना

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। अपने संदेश में धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने शुरूआत से ही इस पूरे घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की थी और कभी भी परिस्थितियों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से उन्हें व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचा है, लेकिन यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में बने हालात का कोई भी राष्ट्रविरोधी तत्व फायदा न उठा सके और देश की एकता एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। धर्मेद्र प्रधान

ने अपने विस्तृत संदेश में कहा कि वह पिछले चार दशकों से छात्र, शिक्षक और शि्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनके अनुसार, एक मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। उन्होंने देश के युवाओं की आकांक्षाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं के सपनों को साकार करना सार्वजनिक जीवन का नैतिक दायित्व है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश की सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए सम्मान की बात रही।

शिक्षा को कारोबार बनाने का आरोप, मनुस्मृति के उल्लेख पर राज्यसभा में हंगामा

एजेंसी

नई दिल्ली। राज्यसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण शिक्षा एक बड़े कारोबार में बदल गई है और इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब परिवारों के बच्चों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मनुस्मृति

का उल्लेख किया और कहा कि शिक्षा में वंचित वर्गों के साथ भेदभाव किया जाता था। मनुस्मृति का उल्लेख किए जाने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिससे सदन में हंगामा हो गया। खड़गे के इस वक्तव्य पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, ह्अभी नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो वक्तव्य दिया है, उससे समाज में द्वेष की भावना पैदा होती है और अशान्ति का वातावरण बनता है। हम सभी इस सदन के जिम्मेदार सदस्य हैं। जहां तक

मेरी जानकारी है, उन्होंने जो बातें कही हैं, वे तथ्यों से परे हैं।ह्अ खड़गे ने कहा कि शिक्षा अब एक बड़ा कारोबार बन चुकी है। निजी शिक्षण संस्थानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और इसकी वजह से गरीब परिवारों के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 70,000 से अधिक है, जिनमें लगभग 4 करोड़ 50 लाख छात्र अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के

छात्रों का नामांकन आज भी राष्ट्रीय औसत से कम है।

उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांग छात्रों की भागीदारी केवल 0.12 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति उस सोच का प्रतीक है, जो शिक्षा को सबका अधिकार नहीं बल्कि कुछ लोगों का विशेषाधिकार मानती है। उनके अनुसार सरकार की नीतियां बार-बार उस मनुवादी सोच की याद दिलाती हैं, जिसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। इसके बाद खड़गे ने कहा

कि वह मनुस्मृति का एक श्लोक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन संस्कृत अच्छी तरह नहीं पढ़ पाने के कारण उसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे।जैसे ही उन्होंने इसका उल्लेख शुरू किया, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध जताना शुरू कर दिया और सदन में शोर-शराबा होने लगा।

हंगामे के बीच सभापति ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यदि किसी सदस्य को आपत्ति है तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन भाषण विचाराधीन हो जाएगा, लेकिन भाषण विचाराधीन हो जाएगा, लेकिन भाषण विचाराधीन

खड़गे से अपना भाषण शीघ्र पूरा करने का भी आग्रह किया। इसके बाद खड़गे ने कहा कि उन्होंने अपने भाषण में शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई तथ्य रखे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार समान और न्यायपूर्ण शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों में अच्छे शिक्षकों और कुलपतियों की नियुक्ति की बात करती है, लेकिन पाठ्यक्रम में जिन बातों को शामिल किया जा रहा है, वे चिंता का विषय हैं। इसके बाद उन्होंने

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक

www.xperttimes.com

विद्या बालन की चर्चित फ्रैंचाइजी पर यामी गौतम ने मारा झपट्टा! कहानी 3 में आएंगी नजर? शूटिंग की तैयारी शुरू



चर्चित फ्रैंचाइजी की तीसरी कड़ी कहानी 3 में यामी गौतम की एंट्री की खबर है। फिल्म का निर्देशन सुजाँय घोष करेंगे। यामी गौतम के सितारे बुलंदी पर हैं। हाल ही में फिल्म आर्टिकल 370 में शानदार अदाकारी के लिए यामी गौतम के नाम का एलान नेशनल फिल्म अवॉर्ड के लिए हुआ। उन्होंने 2024 में आई इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इस बीच अभिनेत्री के फैंस के लिए एक और खुशखबरी है। यामी गौतम फिल्म कहानी 3 में नजर आएंगी। सुजाँय घोष की चर्चित फ्रैंचाइजी की दो फिल्में आ चुकी हैं। पहली फिल्म कहानी साल 2012 में रिलीज हुई थी। वहीं, दूसरा पार्ट 2016 में रिलीज हुआ। दोनों फिल्मों के निर्देशन का जिम्मा सुजाँय घोष ने निभाया। वहीं, लीड रोल में विद्या बालन नजर आई थीं। अब सुजाँय इसकी तीसरी किस्त लेकर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कहानी 3श् में यामी गौतम की एंट्री हो गई है। खबरों के मुताबिक अभिनेत्री यामी गौतम कहानी 3श् में मुख्य भूमिका निभाएंगी। वहीं, सुजाँय घोष एक बार फिर डायरेक्टर के तौर पर वापसी करेंगे। यह फिल्म इस फ्रैंचाइजी की दुनिया में एक नई कहानी दिखाएगी। कहा जा रहा है कि टीम इसकी शूटिंग के शेड्यूल की तैयारी कर रही है। फिल्महाल प्रोजेक्ट अभी प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है। टीम फिल्म के दूसरे पहलुओं पर काम कर रही है। पिकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, पहली दो फिल्मों में विद्या बालन लीड रोल में थीं, लेकिन कहानी 3 इस फ्रैंचाइजी को एक नई दिशा में ले जाएगी। कहा जा रहा है कि यह फिल्म पिछली फिल्मों की कहानी को आगे नहीं बढ़ाएगी, बल्कि कहानी की दुनिया पर आधारित एक नई कहानी होगी। मेकर्स अभी शूटिंग की टाइमलाइन पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही शेड्यूल तय कर लेंगे। यामी को आखिरी बार उनके पति निर्देशक आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म श्धुरंधर- द रिवेंज (2026) में एक कैमियो रोल में देखा गया था।

बिहार के सरकारी स्कूलों में अब भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका में भी होगी पढ़ाई



उमा सक्सेना
पटना: बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने निर्देश दिया है कि अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को हिंदी के साथ-साथ स्थानीय

क्षेत्रीय भाषाओं—भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका—में भी पढ़ाया जाएगा। यह निर्देश शिक्षा मंत्री ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई होने से बच्चे विषयों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उनकी सीखने की क्षमता में सुधार होगा।

मातृभाषा में शिक्षा से बढ़ेगी समझ: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि क्षेत्रीय भाषा बच्चे की पहली भाषा होती है। जब छात्र अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे तो उनकी विषयों में रुचि बढ़ेगी, अवधारणाएं बेहतर तरीके से समझ आएंगी और वे लंबे समय तक उन्हें याद रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए लाभदायक साबित होगी, जहां बड़ी संख्या में बच्चे अपनी स्थानीय भाषा में संवाद करते हैं।

SCERT को मिली अहम जिम्मेदारी: सरकार ने इस नई व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी रजएफ्ट को सौंपी है। परिषद जल्द ही क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार करने, पाठ्यपुस्तकों के विकास और शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके अलावा, SCERT में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी। रिक्त पदों की पहचान कर बिहार लोक सेवा आयोग को अध्यायचना भेजी जाएगी, जिसके बाद आयोग इन पदों पर भर्ती करेगा।

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर: शिक्षा विभाग का मानना है कि क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी और छात्रों के स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर में भी कमी आएगी। साथ ही यह निर्णय बिहार की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करेगा। सरकार जल्द ही इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना और समयसीमा जारी करेगी। इसे बिहार में बहुभाषी शिक्षा नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

ईवा ग्रोवर के शॉकिंग खुलासे: आमिर खान के माई हैदर अली ने बिजली बिल भरने के लिए दूसरों के संग सोने को कहा

बॉलीवुड



इस समय टीवी एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल, उन्होंने अपने एक्स—हसबैंड हैदर अली खान के बारे में खुलकर बात रखी है। आपको बता दें कि, हैदर, आमिर के सौतेले भाई हैं। एक्ट्रेस ने बताया है कि हैदर उन पर डायरेक्टर्स के साथ इटिमेंट होने का दबाव डालते थे। आपको याद होगा टीवी सीरियल करिश्मा का करिश्मा इसमें एक्ट्रेस नजर आ चुकी हैं। इसी के साथ ईवा रेडी मूवी में काम कर चुकी हैं। इस दौरान ईवा ने अपनी मुश्किल शादीशुदा जिंदगी के बारे में खुलकर बात रखी है। हालिए में सिद्धार्थ कन्नन के साथ उनकी बातचीत हुई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या हैदर चाहते थे कि वह दूसरों के साथ शिफ्टजिकली इटिमेंट हों। इस पर एक्ट्रेस ने कहा, उन्होंने ऐसी बात रखी थी, मुझ पर बहुत दबाव डाला था। इसके बाद एक्ट्रेस से पूछा गया है कि क्या हैदर ने उन्हें डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ सोने के लिए मजबूर किया था, जिससे उन्हें काम मिल सके। बातचीत में ईवा ने बताया कि शकाम तो मेरे पास हमेशा था। लेकिन जो फेंज जिसमें मैंने काम छोड़ दिया था, मेरे सारे एफडी तोड़ दिए थे मैंने, गाड़ियां बेच दी थी उसके परिवार के लिए, सब कर लिया था जब मैंने दूसरी बार इनको संभाला था। तो उनकी तरफ से ये ऑफर आया था। टीवी एक्ट्रेस ईवा ने आगे बताया कि, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमको प्रपोजल आते थे ना, एक्ट्रेस से को तो तो आते ही हैं। बड़े—बड़े प्रपोजल आते हैं। मेरे अपने पति ने कहा था, क्या फर्क पड़ता है? करो। करना पड़ेगा। आपको घर चलाना है, हमारा बिजली बिल इतना हो गया है... बच्चे के लिए पैसा चाहिए। वह सब कुछ का अंत था। उसके बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। इस बातचीत में एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि हैदर को सजोफ्रेनिया है, लेकिन जब उनकी शादी हुई तो वह उसकी स्थिति को समझ नहीं पाई क्योंकि वह उसे बमुश्किल जानती थी। उन्होंने खुलासा किया कि उसकी शादी जल्द ही हिंसक हो गई है और उसके शरीर पर चोट के निशान देखने बाद के उसका परिवार उसके लिए चिंतित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि खुलासा किया कि हैदर आज अच्छी जिंदगी नहीं जा रही है। शहनाज की पहली शादी से बेटा हैदर हुआ है। शहनाज ने सुपरस्टार आमिर खान के दिवंगत फिल्ममेकर पिता ताहिर हुसैन से शादी की, इसलिए वह आमिर खान के सौतेले भाई हैं। एक्टर बनने से पहले हैदर ने केबिन वरू मेंबर के तौर पर कार्य किया है। मीडिया रिपोर्ट्स और ईवा के अनुसार, वह आमिर खान के परिवार के बिल्कुल करीब नहीं है।



‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ ने पूरे किए 18 साल

उमा सक्सेना
मुंबई: भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय और लंबे समय तक चलने वाले कॉमेडी शो में शामिल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ ने अपने सफल प्रसारण के 18 साल पूरे कर लिए हैं। 28 जुलाई 2008 को शुरू हुए इस शो ने लाखों दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। शो के 18वें स्थापना दिवस के मौके पर निर्माता असित कुमार

कोदी ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इस अवसर को पूरी टीम ने ‘हंसो और हंसाओ दिवस’ के रूप में मनाया और शो की शानदार यात्रा का जश्न मनाया। ‘जेठालाल’ और ‘बबीता जी’ रहे आकर्षण का केंद्र: सेलिब्रेशन के दौरान शो के लोकप्रिय किरदार ‘जेठालाल’ (दिलीप जोशी) और ‘बबीता जी’ (मुनमुन दत्ता) ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। दोनों कलाकारों ने पूरी स्टारकास्ट के साथ केक काटा, जश्न मनाया और मीडिया से बातचीत में शो से जुड़ी कई यादें साझा कीं। कलाकारों ने दर्शकों के प्यार और समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि यही स्नेह शो की सबसे बड़ी ताकत रहा है, जिसने इसे 18 वर्षों तक लगातार लोकप्रिय बनाए रखा।

18 वर्षों से दर्शकों का पसंदीदा शो: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ भारतीय टेलीविजन का सबसे लंबे समय



तक प्रसारित होने वाले कॉमेडी शो में से एक है। परिवार, सामाजिक संदेश और हल्के-फुल्के हास्य के मेल ने इस

शो को हर उम्र के दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया है। 18 साल पूरे होने के इस खास मौके पर शो की पूरी टीम

योगी सरकार का बड़ा शिक्षा अभियान: पढ़ाई में पीछे छूटे बच्चों के लिए शुरू होगा ‘कैच-अप शिक्षण अभियान’

उमा सक्सेना
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाने और पढ़ाई में पीछे रह गए बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ‘कैच-अप शिक्षण अभियान’ को नई गति देने जा रही है। इस अभियान के तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों, ब्लॉक संसाधन केंद्र, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 31 जुलाई तक सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अभियान का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करना है जो अपने कक्षा स्तर के अनुसार सीखने में पीछे हैं और उन्हें विशेष शिक्षण के माध्यम से आवश्यक अधिगम स्तर तक पहुंचाना है।

15 सूत्रीय रणनीति से सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था: कैच-अप शिक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है। इसके तहत सबसे पहले उन बच्चों

की पहचान की जाएगी जिनका अधिगम स्तर अपेक्षित मानकों से कम है। इसके बाद विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार समूहों में विभाजित कर विशेष शिक्षण दिया जाएगा। रणनीति में गतिविधि आधारित शिक्षण, शिक्षण-अधिगम सामग्री का प्रभावी उपयोग, नियमित अभ्यास, सतत मूल्यांकन और छात्रों की प्रगति की लगातार निगरानी पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही अभिभावकों की भागीदारी भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।

‘निपुण लक्ष्य’ के तहत तय होंगे सीखने के मानक: सरकार के ‘निपुण लक्ष्य’ कार्यक्रम के तहत बालवाटिका से कक्षा 5 तक भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी विषयों के स्पष्ट अधिगम मानक निर्धारित किए गए हैं। इन मानकों के आधार पर शिक्षकों को बच्चों की सीखने की प्रगति का आकलन करने में सुविधा होगी। स्कूलों में लगाए जाने वाले पोस्टरों और IEC सामग्री के माध्यम से प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित अधिगम स्तर की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे शिक्षक और अभिभावक दोनों

बच्चों की प्रगति को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।

रीडिंग के पेन को मिलेगा बढ़ावा: अभियान के तहत रीडिंग के पेन को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्कूलों में रीडिंग कॉर्नर, कहानी वाचन, पुस्तक चर्चा और पढ़ने की आदत विकसित करने वाली गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि पढ़ने की मजबूत क्षमता बच्चों के समग्र शैक्षणिक विकास का आधार है।

क्या है IEC सामग्री?: IEC (Information, Education and Communication) सामग्री का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तक शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। पोस्टर, चार्ट, प्लेक्स और अन्य शैक्षणिक सामग्री के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित

ने दर्शकों का धन्यवाद किया और आने वाले समय में भी इसी तरह मनोरंजन जारी रखने का भरोसा जताया।



किया जाएगा और शिक्षकों को प्रभावी कक्षा शिक्षण की दिशा मिलेगी।

पूरे प्रदेश में एक जैसी शैक्षणिक कार्य संस्कृति विकसित करने का लक्ष्य: राज्य सरकार का कहना है कि कैच-अप शिक्षण अभियान से पूरे उत्तर प्रदेश में एक समान शैक्षणिक कार्य संस्कृति विकसित होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा सीखने में पीछे न रह जाए और प्रत्येक छात्र अपनी कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर हासिल कर सके। सरकार को उम्मीद है कि यह अभियान न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता को भी मजबूत बनाएगा।

(4) हिन्दी मासिक एक्सपर्ट टाइम्स

पाकिस्तान आर्मी पर अंधा भरोसा न करे अमेरिका

विशेषज्ञ ने हाइब्रिड सिस्टम पर दी बड़ी चेतावनी

(एजेंसी)

एक नई रिपोर्ट में, पाकिस्तान में कमजोर होते लोकतंत्र और सेना के बढ़ते असर को लेकर अमेरिका से बड़ा कदम उठाने की अपील की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका को पाकिस्तान के सेना प्रमुख फ़ैज़द मार्शल आसिम मुनीर को मिल रहे समर्थन पर फिर से विचार करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की असल ताकत चुनी हुई सरकार के बजाय सेना के प्रभाव वाली हाइब्रिड राजनीतिक व्यवस्था के हाथ में है, जिससे लोकतांत्रिक सिस्टम पूरी तरह कमजोर पड़ रहा है।

2024 के चुनावों के बाद गहराया संवैधानिक संकट टाइम्स ऑफ़ इज़रायल में राजनीतिक शोषकर्ता वास शेनाय के छपे एक लेख के अनुसार, 2024 के

ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान बुरा फँसा, आसिम मुनीर की सीक्रेट डील के खुलासे से चारों ओर हड़कण

(एजेंसी)

पश्चिम एशिया में लगभग पाँच महीने से भड़की ईरान-अमेरिका जंग अब वैश्विक ऊर्जा, समुद्री व्यापार और महाशक्तियों की प्रतिष्ठा की निर्णायक लड़ाई बन चुकी है। इसी बीच पाकिस्तान एक बार फिर स्वयं को मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका यह नया दांव शुरू से ही कमजोर दिखाई देता है। पहले ही अनेक कूटनीतिक मोर्चों पर संतुलन साधने में विफल रहा इस्लामाबाद अब चीन के इशारे पर ईरान और अमेरिका के बीच रुकी की गतिविधियाँ और शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई बैठकों ें इस प्रयास की गति तो दी है, लेकिन जमीनी हालात इसके गुप्त बिल्कुल विपरीत हैं। एक ओर ईरान समर्थित हूती संगठन सऊदी अरब के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है,

टैक्स रिफॉर्म की दिशा में 5 प्राथमिकताओं पर जोर

टैक-ड्रिवन बनेगा नया इनकम टैक्स सिस्टम

(एजेंसी)

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आयकर विभाग के अधिकारियों से ईमानदार करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने और जानबूझकर कर चोरी करने वालों के खिलाफसख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही सीतारमण ने उम्‍दरादारी कर प्रशासन के लिए प्‍हचान, प्रतिक्रिया, निवारण, समीक्षा और सुधार रूपी पांच प्राथमिकताओं पर विशेष जोर दिया। वित्त मंत्री ने 167वें आयकर दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि विभाग की भूमिका अब केवल कर संग्रह तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें पारदर्शिता, दक्षता, व्यापार सुगमता और सेवा भाव भी शामिल हो गया है। उन्होंने कहा डेढ़ सदी से अधिक समय में आयकर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 132.4 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 1,075 करोड़ रुपये हुआ

(एजेंसी)

नयी दिल्ली। 25 जुलाई निजी क्षेत्र के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 132.4 प्रतिशत बढ़कर 1,075 करोड़ रुपये हो गया। यह बैंक का किसी तिमाही में अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ है। बैंक ने शनिवार को शेयर बाजार को अप्रैल-जून 2026 तिमाही के नतीजे की सूचना दी। एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 463 करोड़ रुपये था। बैंक का कुल ग्राहक कारोबार 30 जून, 2026 तक 18.6 प्रतिशत बढ़कर 6,04,776 करोड़ रुपये हो गया, जो एक वर्ष पहले 5,10,031 करोड़ रुपये था। बैंक ने कहा कि उसकी ऋण एवं अग्रिम राशि 30 जून, 2026 तक 20.6 प्रतिशत बढ़कर 3,05,370



करोड़ रुपये हो गई, जो 30 जून, 2025 को 2,53,233 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन तिमाही के अंत तक बैंक का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात घटकर 1.51 प्रतिशत रह गया, जो वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 1.97 प्रतिशत

सुरक्षा चुनौतियों को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है।

आर्थिक तंगी, कर्ज और बढ़ती गरीबी का बोझ

आर्थिक मोर्चे पर रिपोर्ट कहती है कि अंतरराष्ट्रीय मदद से पाकिस्तान का तुरंत डूबने का खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन वह अब भी भारी कर्ज, ऊर्जा संकट और विदेशी फंड्स पर निर्भर है। तेजी से बढ़ती आबादी, गरीबी और जलवायु परिवर्तन जैसी परेशानियां देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कमजोर बना रही हैं।

अमेरिका को सुझाव विशेषज्ञ ने सलाह दी है कि अमेरिका को पाकिस्तान को आर्थिक और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी मदद देनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कुछ सख्त शर्तें भी लगानी चाहिए। जैसे, देश में निष्पक्ष और आजाद चुनाव कराए जाएं। नागरिक सरकार



को मजबूत किया जाए। सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई हो। लेख में साफ कहा गया है कि वॉशिंगटन को पहले की तरह पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व को आंख मूंदकर समर्थन देने से बचना चाहिए।

परमाणु हथियारों की सुरक्षा रिपोर्ट में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का भी जिक्र किया गया

मौजूदा कूटनीतिक पहल को कई विश्लेषक निष्पक्ष शांति प्रयास की बजाय क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और अपने रणनीतिक हितों को साधने की कोशिश के रूप में भी देख रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की कूटनीतिक कवायद बेहद कठिन संतुलन की मांग करती है। एक ओर वह सऊदी अरब की आर्थिक सहायता पर निर्भर है, वहीं दूसरी ओर चीन उसका सबसे बड़ा रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है। उधर, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के विरुद्ध नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा कर दी है और तेल टैंकरों को निशाना बनाकर पूरे क्षेत्र में तनाव कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान यदि ईरान के अधिक निकट खिड़ा देता है तो सऊदी अरब नाराज हो सकता है, जबकि चीन चाहता है कि किसी भी कीमत पर क्षेत्र में शांति स्थापित हो ताकि उसके व्यापारिक और ऊर्जा हित सुरक्षित रह सकें। हम आपको बता दें कि चीन की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार है।

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने टेक्सास से लॉन्च किया सबसे शक्तिशाली स्टारशिप रॉकेट

का नागरिक और देश के विकास का साझेदार भी है। उन्होंने कर विवादों को कम करने और कर निश्चितता बढ़ाने पर भी जोर दिया। कर् निश्चितता स्पर्च्छक अनुपालन की मजबूत नींव है। हमें ‘विवाद प्रबंधन’ से आगे बढ़कर ‘विवाद रोकथाम’ की दिशा में काम करना होगा। इस मौके पर राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 2.24 लाख अपीलों का निपटान किया गया, जो एक साल पहले से 30 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि विभाग वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। वित्त मंत्री ने आयकर अधिकारियों से कहा कि कर कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग हमेशा विनम्रता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि करदाता केवल कर आकलन का विषय न होकर देश

(एजेंसी)

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फिर से कहा कि तेहरान अमेरिकी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकेगा और देश किसी भी तरह के जबरदस्ती या बल-प्रयोग को स्वीकार नहीं करेगा। प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, किर्गिस्तान के चोलपोन-अता में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के बाद प्रकाशों से बात करते हुए अरागची ने राजनयिक माध्यमों से जुड़ी चर्चाओं पर बात की। बैठक के दौरान हुई द्विपक्षीय

बातचीत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच मुख्य बाधा बातचीत के रास्तों की कमी नहीं है, बल्कि अमेरिका का धौंस जमाने और जबरदस्ती करने पर लगातार निर्भर रहना है। अरागची ने जोर देकर कहा कि ईरान ने दिखा दिया है कि वह अमेरिका की धौंस के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

स्पेन में आग का संकट: 70 हजार लोगों ने छोड़ा घर मैड्रिड में धुएं का गुबार , प्रशासन ने जारी किया इमरजेंसी अलर्ट

(एजेंसी)

स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सॉंचेज ने शनिवार को बताया कि मैड्रिड के पश्चिमी इलाके में लगी भीषण आग पर काबू पाने और लोगों की जान बचाने के लिए दमकलकर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं। तेज हवाएं चलने की आशंका ने इस राहत और बचाव काम को और भी ज्यादा कठिन बना दिया है।

70 हजार लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर सरकारी जानकारी के मुताबिक, सूखे इलाकों में फैली इस आग की वजह से करीब 70,000 लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। स्थानीय अधिकारियों ने इसे इस पूरे इलाके के इतिहास की अब तक की सबसे भयानक और विनाशकारी आग करार दिया है। आने वाले कुछ घंटे हो सकते

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना ईरान को अर्थव्यवस्था बचाने में मदद नहीं मिलेगी



इन उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि राजस्व की सुरक्षा के साथ कर विवादों का तेजी और अधिक दक्षता से निपटान किया जा सके। वहीं, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि शिकायतों के समाधान में भी सुधार हुआ है और करने पर भी काम कर रहा है, ताकि कहा कि पिछले वित्त वर्ष में विभाग के प्रयास किए हैं। श्रीवास्तव ने कहा,

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना ईरान को अर्थव्यवस्था बचाने में मदद नहीं मिलेगी

(एजेंसी)

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फिर से कहा कि तेहरान अमेरिकी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकेगा और देश किसी भी तरह के जबरदस्ती या बल-प्रयोग को स्वीकार नहीं करेगा। प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, किर्गिस्तान के चोलपोन-अता में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के बाद प्रकाशों से बात करते हुए अरागची ने राजनयिक माध्यमों से जुड़ी चर्चाओं पर बात की। बैठक के दौरान हुई द्विपक्षीय बातचीत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच मुख्य बाधा बातचीत के रास्तों की कमी नहीं है, बल्कि अमेरिका का धौंस जमाने और जबरदस्ती करने पर लगातार निर्भर रहना है। अरागची ने जोर देकर कहा कि ईरान ने दिखा दिया है कि वह अमेरिका की धौंस के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी हाल में बल, दबाव और धमकियों



की भाषा का जवाब नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अलग-अलग प्रस्तावों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करना एक स्वाभाविक कदम है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तेहरान का मुख्य स्ख बताते हुए अरागची ने कहा कि ईरानी लोगों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के हितों की रक्षा करना हमारे सिद्धांतों में शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरानी लोगों के जायज मकसद और मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम स्वाभाविक रूप से अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने आगे

कहा, हम धमकियों से डरते नहीं हैं, न ही दबाव में झुकेंगे, और हम धमकी भरी भाषा बदोश्त नहीं करेंगे। अरागची ने कहा कि ईरान की सेनाएं मोर्चे पर और उसके राजनयिक अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की सेवा में एक-दूसरे के पूरक की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने ब् (जिसे उन्होंने एक प्रगतिशील संगठन बताया) के सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे वाशिंगटन और उन पश्चिमी संस्थाओं के एकरूपता एजेंडे का मुकाबला करें जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर हावी होना चाहती हैं।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना ईरान को अर्थव्यवस्था बचाने में मदद नहीं मिलेगी



हैं बेहद मुश्किल

प्रभावित इलाके से सेनिसीएंटोस गांव पहुंचे पीएम सॉंचेज ने कहा, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता और मकसद लोगों की जान बचाना और रिहाइशी इलाकों की सुरक्षा करना है। उन्होंने आगे सावधान करते हुए कहा, आने वाले कुछ घंटे के इतिहास की भरें हो सकते हैं। भले ही तापमान थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हवा की रफ्तार और उसकी दिशा को

लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।

हर तरफतबाही का मंजर क्रुनेट शहर की मेयर मार निकोलस ने हालात पर चिंता जताते हुए कहा, इस इलाके में हर साल आग की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार का रूप बेहद खोफ्नाक है। यह एक बहुत बड़ी तबाही है।

मैड्रिड की सड़कों तक फैला धुआं

(एजेंसी)

ज्यादा खर्चों के कारण ज़िंदल स्टील का जून तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 43.53 प्रतिशत घटकर 843.80 करोड़ रुपये रह गया। इस्पात कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को अप्रैल-जून 2026 तिमाही के नतीजे की सूचना दी। पिछले साल की इसी तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा 1,495.97 करोड़ रुपये था। हालांकि, इस अवधि में कंपनी में आय बढ़कर 15,501.32 करोड़ रुपये हो गई जो वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 12,324.88 करोड़ रुपये थी। आलोच्य अवधि में ज़िंदल स्टील का खर्च 14,296.36 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान तिमाही में यह शिकायतों के मूल कारणों को दूर करने पर भी काम कर रहा है, ताकि करदाताओं को शुरुआत में ही कम 2026 तक अपना एकीकृत शुद्ध



कर्ज घटाकर 15,927 करोड़ रुपये कर दिया है जो मार्च 2026 में 16,019 करोड़ रुपये था। नवीन ज़िंदल समूह की कंपनी ने कहा कि तिमाही के लिए कुल पूंजी परिव्यय 1,959 करोड़ रुपये था। इस तिमाही में उसका कच्चा इस्पात उत्पादन 15 प्रतिशत बढ़कर 24 लाख टन हो गया, जो वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 20.9 लाख था। बिक्री 17 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 22.3 लाख टन हो गई।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना ईरान को अर्थव्यवस्था बचाने में मदद नहीं मिलेगी



इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिससे स्पेसएक्स के पास दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह समूह है। नए प्रक्षेपित स्टारलिनक उपग्रहों में से छह पर कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों ने उड़ान के अंत में स्टारशिप की ‘हीट शील्ड’ की तस्वीरें लीं और अंतरिक्षयान के समुद्र में लहरों के बीच तैरते रहने के बावजूद बेहद

स्पष्ट तस्वीरें सफलतापूर्वक भेजीं। ‘हीट शील्ड’ पर ऐसे सेंसर भी लगाए गए थे जो प्रक्षेपण के दौरान नए प्रक्षेपित स्टारलिनक उपग्रहों से छह पर कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों ने उड़ान के अंत में स्टारशिप की ‘हीट शील्ड’ की तस्वीरें लीं और अंतरिक्षयान के समुद्र में लहरों के बीच तैरते रहने के बावजूद बेहद

स्वत्वाधिकारी एक्सपर्ट टाइम्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक, सम्पादक जितेन्द्र कुमार द्वारा शॉप नम्बर-2 प्लॉट नम्बर-17, ग्राउण्ड फ्लोर, ब्लॉक एल-3, नियर भोला चौक, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110059 से प्रकाशित एवं मुद्रक दिनेश शर्मा द्वारा स्वास्तिका क्रीएशन 19 डीएसआईडीसी रोड्स, स्क्रीम 3, ओखला फेज-2 नईदिल्ली-110020 से मुद्रित। रजिस्ट्रेशन नं०- DLBIL/26/A3806 मो० नं०- 9266066092

❖पीआरबी एक्ट के अंतर्गत सभी विवादों का न्याय क्षेत्र द्वारका कोर्ट दिल्ली होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित लेख अथवा समाचार से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।